



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 ज्येष्ठ 1940 (श10)
(सं० पटना 459) पटना, बुधवार, 23 मई 2018

सं० 3/मुक०-1076/2016-707
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

22 मई 2018

विषय— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2006 में 2277 नवसृजित चतुर्थवर्गीय तकनीकी पदों के विरुद्ध नियुक्त वैसे कर्मियों जो पूर्व में कार्यभारित स्थापनान्तर्गत नियुक्त हुए तथा वर्ष 2002 ई० में श्रमपुस्त पर रखे जाने के उपरान्त वर्ष 2006 में समायोजित हुए, की विभागीय पत्रांक-925 दिनांक 16.11.13 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-10710 दिनांक 17.10.13 के आलोक में श्रमपुस्त पर बितायी गयी कार्य अवधि को सतत् कार्यभारित अवधि मानते हुए वेतन संरक्षण, ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०, सेवान्त लाभ एवं अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अनेक जलापूर्ति योजनाएं चलायी जाती हैं। इन जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु तकनीकी कर्मियों का पद स्वीकृत नहीं रहने के कारण वर्ष 1980-82 के बीच दैनिक श्रमपुस्त कर्मियों को रखकर कार्य कराया जा रहा था। इन श्रमपुस्त कर्मियों को वर्ष 1982-88 के बीच विभिन्न अवधियों में कार्यभारित स्थापनान्तर्गत लाया गया। वित्त विभागीय संकल्प संख्या-6394 दिनांक 23.10.87 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल रहने के कारण इन कर्मियों को वर्ष 2002 ई० में विभागीय पत्रांक-2322 दिनांक 13.04.02 के द्वारा दैनिक श्रमपुस्त पर रखा गया।

2. उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध कतिपय कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिकाएं दायर की गयीं। सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-7359/2002 राम तपेश्वर साह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में 164 याचिकाओं के साथ समेकित रूप से पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा मामले पर विचार करते हुए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर विभाग के अधीन 2277 पदों का सृजन अधिसूचना संख्या-301, 302 एवं 303 दिनांक 29.07.2006 के द्वारा किया गया। इन नवसृजित पदों के विरुद्ध विभागीय पत्रांक-1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134 एवं 1135 दिनांक 28.11.06 के द्वारा विभाग में

कार्यरत दैनिक श्रमपुस्त कर्मियों को स्वीकृत एवं रोस्टर बिन्दु के अनुसार कर्णांकित पदों के विरुद्ध प्रमंडलवार समायोजन हेतु अनुशंसा की गयी। उक्त अनुशंसा के आलोक में इन कर्मियों का समायोजन संबंधित प्रमंडलों के स्तर से किया गया। वर्ष 2002-06 तक की श्रमपुस्त अवधि को कार्यभारित अवधि माने जाने एवं सभी अनुषांगिक लाभ के लिए समायोजित कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गयीं, यथा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-14959/13,, 15919/13, 16742/13, 15158/13, 21887/13, 15990/13, 15276/13, 15817/13, 16912/13, 5840/11, 975/12, 16448/11, 7178/10, 15870/11, 8924/10, 11311/16, 11290/16, 13982/16, 11098/16, 16494/16, 18380/16। संबंधित याचिकाओं में विभाग के प्रतिकूल आदेश पारित हुआ है और इन मामलों में न्यायिक अवमाननावाद की बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण विभाग द्वारा न्यायादेश का अनुपालन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-13340/15 एवं 13369/15 में भी प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.11.13 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-924 दिनांक 16.11.13 एवं अनुवर्ती विभागीय ज्ञापांक-925 दिनांक 16.11.13 द्वारा दिनांक 01.06.02 से समायोजन की तिथि दिनांक 30.11.06 तक की दैनिक पारिश्रमिक पर बितायी गयी कार्य अवधि को कार्यभारित अवधि माने जाने का आदेश पारित है।

4. अतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2006 में 2277 नवसृजित चतुर्थवर्गीय तकनीकी पदों के विरुद्ध नियुक्त वैसे कर्मी जो पूर्व में कार्यभारित स्थापनान्तर्गत नियुक्त हुए तथा वर्ष 2002 ई० में श्रमपुस्त पर रखे जाने के उपरांत वर्ष 2006 में समायोजित हुए, को विभागीय पत्रांक-925 दिनांक 16.11.13 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-10710 दिनांक 17.10.13 के आलोक में श्रमपुस्त पर बितायी गयी कार्य अवधि को सतत् कार्यभारित अवधि मानते हुए उन्हें वेतन संरक्षण, ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०, सेवान्त लाभ एवं अन्य सभी अनुषांगिक लाभ प्रदान करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-1802 दिनांक 23.03.06 के अलोक में कार्यभारित अवधि की गणना ए०सी०पी० के प्रयोजनार्थ की जा सकेगी। इस ए०सी०पी० का लाभ ए०सी०पी० नियमावली-2003 के निरसन की तिथि 13.07.2010 के ठीक पूर्व दिनांक 12.07.2010 तक ही अनुमान्य किया जा सकेगा। पेंशन एवं गेच्युटी लाभ की गणना वित्त विभागीय संकल्प सं०-10710 दिनांक 17.10.13 की कंडिका-5(V) में विहित प्रावधानों के आलोक में की जा सकेगी।

आदेश से,
विनय कुमार,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 459-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>